साप्ताहिक
Live not just breaTHE
दि कॉस्मिक पोस्ट
MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23
Global School Of Excellence, Obedullaganj
वर्ष : 10, अंक : 8 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 9 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

बदलती जलवायु में शहरों को गर्म व ठंडा करने के लिए ऊर्जा की मांग में होगी भारी बढ़ोतरी

मुंबई। एक नए अध्ययन में ऊर्जा को लेकर लगाए गए अनुमानों के अनुसार, यदि भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जारी रहा तो साल 2099 तक शहरी घरों को गर्म व ठंडा करने (हीटिंग और कूलिंग) प्रणाली पर 50 फीसदी तक जलवायु परिवर्तन का असर पड़ेगा। इसके कारण ऊर्जा की मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगी साथ ही जलवायु में और अधिक बदलाव होगा।

यह अध्ययन मुख्य रूप से ऊर्जा उपयोग, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल के बीच जटिल क्रियाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं। इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की अगुवाई में किए गए शोध में शहरी बुनियादी ढांचे और वायुमंडल के बीच अक्सर अनदेखी की जाने वाली आंतरिक रूप से चलने वाली क्रियाओं पर गौर किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर जलवायु में छोटा सा प्रभाव डालकर, दुनिया भर में जलवायु में बदलाव कर सकते हैं। इस नए अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि आवासीय और व्यावसायिक रूप से गर्म व ठंडा करने के प्रयासों से छोटे पैमाने पर शहरों में बर्बाद होने वाली गर्मी स्थानीय जलवायु और ऊर्जा उपयोग पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा गर्म व ठंडा करने की प्रणाली से उत्पन्न होने वाली गर्मी शहरी इलाकों में उत्पन्न कुल गर्मी का एक बड़ा हिस्सा है। ये प्रणाली बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं जो शहरों के भीतर वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे वे गर्म हो जाते हैं और घरों के अंदर या इनडोर कूलिंग सिस्टम की मांग बढ़ जाती है, जो स्थानीय जलवायु को और अधिक गर्म कर देती है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे शोधकर्ता इमारतों को ठंडा करने की प्रणाली के उपयोग और स्थानीय शहरी वातावरण के गर्म होने के बीच की प्रतिक्रिया लूप कहते हैं। शोधकर्ता इस बात पर भी गौर करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के तहत बढ़ते तापमान से ठंडे महीनों के दौरान ऊर्जा की मांग में कमी आ सकती है। अध्ययन के अनुसार, शहरी घरों को कम गर्म करने से वातावरण में कम गर्मी निकलेगी, जिससे वर्तमान जलवायु की तुलना में शहरों का तापमान कम बढ़ेगा। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, यह प्रक्रिया एक खराब प्रतिक्रिया लूप बनाती है जो गर्म करने की मांग को कम कर सकती है। लेकिन यह किसी भी तरह से अच्छे प्रतिक्रिया लूप प्रभाव को खत्म नहीं करता है। इसके बजाय, मॉडल सुझाव देता है कि यह मौसमी आधार पर बिजली की मांग को और बढ़ा सकता है, जो अपनी तरह की समस्याओं को जन्म देता है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन की बड़ी तस्वीर में इन अनदेखी समस्याओं को शामिल करने के लिए, टीम ने एक हाइब्रिड मॉडलिंग ढांचे का उपयोग किया। यह शहरी जलवायु परिवर्तन और अनिश्चितताओं के तहत दुनिया भर में शहरी घरों को गर्म या ठंडा करने के लिए ऊर्जा की मांग का पता लगाने के लिए तेज पृथ्वी प्रणाली मॉडलिंग और मशीन लर्निंग को जोड़ती है। जिसमें इस कारण उत्पन्न स्थानीय और अन्य चुनौतियां शामिल हैं कि शहर आय, बुनियादी ढांचे, जनसंख्या घनत्व, तकनीक और तापमान को सहने में किस तरह अलग-अलग हैं। अध्ययन के मुताबिक, अच्छा और खराब प्रतिक्रिया लूप के प्रभावों को एक साथ जोड़ने वाले ऊर्जा अनुमानों की जरूरत है और यह अधिक व्यापक जलवायु प्रभाव आकलन, विज्ञान-आधारित नीति निर्माण और जलवायु में बदलाव करने वाली ऊर्जा नियोजन के लिए आधार तैयार करेगा।

शोधकर्ताओं ने शोध के हवाले से कहा कि कैसे नमी, निर्माण सामग्री और भविष्य के जलवायु में बदलाव को कम करने के प्रयासों जैसे अनिश्चितताओं के बावजूद ऊर्जा की मांग के अनुमानों को बेहतर बनाया जा सकता है।

मीथेन उत्सर्जन पर लगाम जरूरी- रिपोर्ट

मुंबई। कई तरह की मानवजनित गतिविधियों के कारण वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जित होती है। कृषि, लैंडफिल, अपशिष्ट जल और जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वितरण इनमें सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। ये दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन का लगभग 60 फीसदी के लिए जिम्मेवार हैं और शेष 40 फीसदी उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की तरह, मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो हाल ही में दुनिया भर में तापमान वृद्धि के 40 फीसदी से अधिक के लिए जिम्मेदार है। हालांकि मीथेन का वायुमंडलीय जीवनकाल केवल 12 साल है, जो सीओ2 से बहुत कम है। इसका मतलब है कि मीथेन उत्सर्जन में कटौती दुनिया भर में तापमान वृद्धि को धीमा करने में सीओ2 की तुलना में तेज प्रतिक्रिया कर सकती है।

अर्थव्यवस्था और जनस्वास्थ्य पर दिखता है गंभीर असर

पिछले सप्ताह भारतीय मीडिया में दो खबरें सुर्खियों में रही थीं। पहली खबर एंटीबायोटिक सहित नकली दवाओं की आपूर्ति के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से जुड़ी थी। इन लोगों पर आरोप हैं कि वे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सरकारी अस्पतालों को घटिया एवं नकली दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। जो गोलियां और टैबलेट अस्पतालों को भेजी गई थीं, उनमें ज्यादातर टैल्कम पाउडर और स्टार्च से तैयार की गई थीं। उनमें कोई औषधीय रसायन था ही नहीं। इसके फौरन बाद इतना ही परेशान करने वाली दूसरी खबर आ गई। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा हाल में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि बाजार में उपलब्ध दवाएं (कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक, एंटैसिड, एंटीपायरेटिक्स और रक्तचाप की दवाएं) गुणवत्ता के मामले में कमजोर थीं। इन दवाओं का लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इनमें कुछ दवाओं का उत्पादन एवं बिक्री हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, एल्केम, टॉरेंट और दूसरी नामी कंपनियां करती हैं। जिन ब्रांडों के नमूने गुणवत्ता के पैमानों पर नाकाम हो गए, उनमें से कुछ तो अपनी-अपनी श्रेणियों में बाजार के अगुआ हैं। भारत में दवा निरीक्षक हर महीने बाजार में उपलब्ध दवाओं की जांच करते रहते हैं। सीडीएससीओ ने लगातार पाया है कि इनमें से कुछ दवाओं के नमूने गुणवत्ता मानकों की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली रिपोर्ट नहीं थी जिसमें कई दवाएं घटिया होने की बात कही गई है। फर्क इतना है कि पहले आई इसी तरह की रिपोर्ट की तुलना में इसमें अधिक विस्तार से बात की गई है। घटिया और नकली दवाओं की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। कुछ वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान जताया था कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बाजारों में बिक रहे 10 चिकित्सा उत्पादों (ज्यादातर दवाएं या टीके मगर स्वास्थ्य उपकरण भी) में से क घटिया या 'फर्जी' की श्रेणी में आता है। भारत अपनी वर्तमान प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से निम्न मध्यम आय वाले देशों में आता है। यह समस्या विकसित या उच्च-आय वाले देशों में भी थोड़ी-बहुत है। घटिया और नकली दवाएं कई कारणों से देश की आर्थिक उत्पादकता एवं वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन प्रभावों की पड़ताल के लिए एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों में कई अध्ययन किए गए हैं। हैरत की बात है कि इस विषय पर भारत में ऐसा एक भी अध्ययन नहीं हुआ है, जो विस्तृत हो या बड़े पैमाने पर नमूने लेकर किया गया हो। तब भी यह समझने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था पर घटिया एवं नकली दवाओं का बड़ा असर क्यों होता है। ये दवाएं बीमारियां ठीक करने में कारगर नहीं होतीं और अक्सर लोगों को अधिक समय तक बीमार रखती हैं। कभी-कभी ये जानलेवा भी साबित होती हैं। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है और कामकाज का नुकसान भी होता है। इससे नौकरी जा सकती है और इलाज के लिए कर्ज भी लेना पड़ जाता है। जिस देश में इलाज के लिए एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर ही देश की बड़ी आबादी की माली हालत खस्ता हो जाती है वहां ऐसी दवाओं की वजह से भारी संख्या में लोग गरीबी के जंजाल में फंस जाते हैं। घटिया और नकली दवाएं किसी भी उम्र के लोगों की जान ले सकती हैं मगर नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनसे लोगों की सेहत को दीर्घकालिक खतरे भी बढ़ जाते हैं जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर होना या दवाओं का रोगाणुओं पर बेअसर होना। निम्न एवं उच्च आय वाले सभी देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है मगर भारत के लिए यह समस्या दो कारणों से ज्यादा ही बड़ी है। पहला कारण भारत की आबादी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, इसलिए यहां समस्याएं भी कई गुना बड़ी हो गई हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में युवा आबादी अधिक है जिसके कई लाभ हैं।

इंदौर शहर की तर्ज पर अब जिले के ग्रामीण क्षेत्र को भी स्वच्छता में बनाया जाएगा अव्वल

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)इंदौर शहर की तर्ज पर अब जिले के ग्रामीण क्षेत्र को भी स्वच्छता में अव्वल बनाया जाएगा। इस संबंध में आज यहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक में संकल्प लिया गया। बैठक में तय किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान चलाकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाएंगे और जन जागरूकता लाई जाएगी। इस कार्य में पंचायत जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का विशेष सक्रिय सहयोग लिया जाएगा।

इस बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री भरत सिंह पटेल सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। पहले चरण में इंदौर जिला देश में अव्वल रहा था। तय किया गया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की पहल पर अभियान के दूसरे चरण का भी प्रभावी क्रियान्वयन जिले में सुनिश्चित किया जाएगा। जिले को इंदौर शहर की तर्ज पर स्वच्छता में अव्वल बनाया जाएगा। बैठक में स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जा रहे हैं कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले में स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चारों विकासखंड में मशीनीकृत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। जिले में 3 हजार से अधिक आबादी वाले 102 ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस व्यवस्था का विस्तार किया जाए और जिले की सभी पंचायतों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएं। श्रीमती महाजन ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार सात बार से अव्वल है हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिले का ग्रामीण क्षेत्र भी स्वच्छता में अव्वल रहे। इस दिशा में सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग/व्यवसाय आदि बड़ी संख्या में स्थापित हो गए हैं, मैरिज गार्डन, फार्म हाउस आदि बन गए हैं, गांवों का विकास शहर जैसा हो रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जरूरी है कि व्यापक कार्य योजना बनाकर स्वच्छता के कार्य व्यापक स्तर पर किये जाएं। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत कार्य योजना जल्दी ही बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टोलियां बनाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाएं और कार्य करें। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर जिले में स्वच्छता के अभियान को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसमें हर तरह का सहयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया जाएगा। किसी भी तरह की धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम जिले को स्वच्छता में जरूर अव्वल बनाएंगे। सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि सबसे पहले इंदौर शहर से लगी ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वच्छ बनाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन की समुचित व्यवस्था के लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से भी संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।

कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का किया वर्चुअली शुभारंभ

स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना में 685 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ भूमि-पूजन और लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस-2024 समारोह में नई दिल्ली से मध्यप्रदेश को अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्वालियर में बनी देश की पहली आधुनिक और आत्म-निर्भर गौ-शाला और परिसर में निर्मित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ भी किया। स्वच्छता दिवस पर कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के राज्य स्तरीय समापन समारोह में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना में 685 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण हुआ। साथ ही नगर निगम भोपाल के उपकरणों तथा विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना अंतर्गत प्रदेश के लिए 685 करोड़ रूपए की लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं के भूमि-पूजन और लोकार्पण के लिए आभार माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर आदर्श गौ-शाला ग्वालियर के 100 टन क्षमता बॉयो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिक व संस्थाओं को सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में नगर निगम उज्जैन को थ्री-स्टार रेटिंग मिलने पर उज्जैन के 2 हजार 115 सफाई मित्रों को प्रोत्साहन स्वरूप 3-3 हजार रुपये की राशि प्रदान करने के लिए 63 लाख 45 हजार रुपये की राशि सिंगल क्लिक से नगर निगम उज्जैन को अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के स्वच्छता मित्रों से वर्चुअली आत्मीय संवाद किया तथा कार्य के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर निगम शासकीय सेवा में कर्तव्य पालन के दौरान दिवंगत 26 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल नगर निगम के 125 नए डोर-टू-डोर सीएनजी वाहनों, 6 नए हुक लोडर, दो श्रेडर मशीन तथा एक लिटर पिकिंग मशीन का अवलोकन किया तथा मंच से झंडी दिखाकर उनका लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा किप्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर भोपाल के मार्गों पर द्वार स्थापित किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति से जुड़े महापुरुषों भगवान राम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, सम्राट अशोक आदि के नाम पर इन द्वारों का नामकरण किया जाएगा। भोपाल नगर निगम द्वारा विकसित किए जा रहे नमो-उपवन को राज्य शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म-दिवस 17 सितम्बर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 10 वर्ष पूर्व 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का विषय उठाना अभिनंदनीय है। भारतीय संस्कृति उत्तम सुख-निरोगी काया के सिद्धांत में विश्वास करती है और स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। हमें स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता कर्मी प्राण-प्रण से समर्पित हैं। उनका कार्य चुनौती भरा और जीवटता वाला है, जैसे सेना का सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देता है उसी प्रकार सफाई कर्मी, स्वच्छता और समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसी का परिणाम है कि 19 सितम्बर को उज्जैन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गाँव-गाँव में शौचालय निर्मित करवाकर महिलाओं को बड़ी समस्या और पीड़ा से राहत पहुंचाई है। राज्य सरकार स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यह कार्य सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में 42 हजार 500 से अधिक स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। प्रदेश में 968 ब्लैक स्पॉट का उन्मूलन और सौन्दर्यीकरण हुआ तथा 800 से अधिक शालाओं में एक लाख से अधिक छात्रों के बीच स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों से जन-जागरूकता फैलाई गई। प्रदेश में नगरीयनिकायों की स्टार रैंकिंग प्रणाली के तहत उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच के परिणाम स्वरुप ही स्वच्छता को जन-आंदोलन का रूप प्रदान किया जा सका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांस्कृतिक गतिविधियों और त्यौहारों के माध्यम से विकास और जन-कल्याण के साथ स्वच्छता को संस्कार के रूप में अंगीकार करने के लिए प्रदेशवासियों को प्रेरित किया है। स्वच्छता को आदत के रूप में अपनाना और स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, संवेदनशील समाज की पहचान है। मध्यप्रदेश देश में स्वच्छतम राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री सारंग ने कहा कि स्वच्छता ही समाज को स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। स्वच्छता सेवा पखवाड़े का उद्देश्य यही है कि सभी को स्वच्छता की आदत हो। स्वच्छता के कार्य में लगे स्वच्छता मित्रों के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान की जिम्मेदारी समाज की है। कार्यक्रम को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गौर तथा नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता दिवस पर स्वच्छता पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में प्रदेश में स्वच्छता के लिए संचालित गतिविधियों, अमृत योजना और रि-ड्यूस- रि-यूज- रि-साइकिल पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदेश को दी गई सौगातों पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही गौ-वंश संरक्षण के लिए प्रदेश में जारी गतिविधियों और स्वच्छता ही सेवा अभियान संबंधी गतिविधियों पर तैयार लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा, विधायक सर्वश्री रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी सहित नागरिक और सफाई मित्र उपस्थित रहे।

राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर

जयपुर। राजस्थान सरकार के ऊपर पर्यावरण कानून का पालन करने में विफल होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (ह्तज्ञ) ने करोड़ों का जुर्माना लगाया है. बताया जाता है कि 17 सितंबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है. ह्तज्ञ ने अपने आदेश में कहा में कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डालने वाले अनुपचारित कचरे के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने में घोर लापरवाही को उजागर करता है.

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मूल आवेदन की सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने राज्य भर में अपशिष्ट प्रबंधन में पर्याप्त अंतर देखा. ट्रिब्यूनल ने कहा कि जहां प्रतिदिन 6,523 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, वहीं इस कचरे का केवल 63.19त्न ही संसाधित होता है, जबकि 2,400 टन कचरा अनुपचारित रह जाता है. इसके अतिरिक्त, 88 मिलियन क्यूबिक मीटर पुराने कचरे में से 71 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक का उपचार नहीं किया जा सका है.

गीले कचरे का भी नहीं हो रहा प्रबंधन

गीले कचरे के संबंध में, एनजीटी ने पाया कि राज्य में सीवेज उपचार में प्रति दिन 628 मिलियन लीटर का अंतर है, जिसमें उत्पन्न 1,550 मिलियन लीटर में से 799 मिलियन लीटर प्रतिदिन संसाधित होता है. ट्रिब्यूनल ने राज्य की अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की और आदेशों का पालन नहीं करने पर 746.88 करोड़ रुपये का कुल पर्यावरणीय मुआवजा लगाया, जिसमें अनुपचारित विरासती कचरे के लिए 633.78 करोड़ रुपये और अनुपचारित सीवेज के लिए ?113.10 करोड़ शामिल हैं.

पंजाब पर भी लगा था 1 हजार करोड़ का जुर्माना

इसके अलावा, इसी मामले में, एनजीटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली, सभी राज्य सरकारों द्वारा गैर-अनुपालन के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रत्येक राज्य को कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया है. 25 जुलाई 2024 के एक हालिया आदेश में, एनजीटी ने इसी तरह के उल्लंघन के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ 1,026 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल निकट भविष्य में अन्य राज्यों के संबंध में फैसले सुनाएगा, जिससे पूरे भारत में राज्य सरकारों द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल मिलेगा.

जलवायु में आते बदलावों का सामना करने के लिए तैयार नहीं भारत सहित दुनिया के कई शहर- रिपोर्ट

नई दिल्ली। आज दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 70 फीसदी तक पहुंच जाएगा। हालांकि जहां शहरों में रहने के अपने फायदे हैं वहीं चुनौतियां भी कम नहीं। देखा जाए तो दुनिया में जिस तेजी से शहरों का विस्तार हो रहा है, वो अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी पैदा कर रहा है।

इतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिस तरह जलवायु में बदलाव आ रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है उसका असर शहरों में भी खुल कर सामने आने लगा है। शहरों में जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से उभरती समस्याओं के साथ-साथ स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभावों को उजागर करते हुए येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, रेसिलिएंट सिटीज नेटवर्क और द रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में न केवल जलवायु परिवर्तन से उभरती समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इससे जुड़े समाधानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। इस रिपोर्ट में 52 देशों में 118 शहरों के 200 नेताओं के पर किए एक सर्वेक्षण को भी शामिल किया गया है। उन लोगों से जलवायु से जुड़े खतरों से निपटने के लिए उनकी तैयारियों के बारे में भी पूछा गया था। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के शहरों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ किए साक्षात्कार को भी इस रिपोर्ट में साझा किया गया है। यदि भारतीय शहरों को बात करें तो इस रिपोर्ट में अहमदाबाद, पुणे, और सूरत शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तेजी से बढ़ती आबादी इन शहरों के लिए समस्या पैदा कर रही है। वहीं हरे-भरे क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जो बढ़ते तापमान के असर को सीमित करने में मददगार होते हैं। इन शहरों के साथ एक बड़ी समस्या इनका पुराना पड़ता बुनियादी ढांचा भी है, जो बाढ़, तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही जलवायु में आता बदलाव स्वास्थ्य समस्याओं को भी पहले से बदतर बना रहा है, उदाहरण के लिए मौसमी बदलावों और बढ़ते तापमान की वजह से डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। देखा जाए तो वो देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहां शहरों को कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन शहरों में कमजोर तबके पर असमान रूप से कहीं ज्यादा असर डाल रहा है, ऐसे में शहरों को इन समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए विद्यार्थी वर्ग की अहम भूमिका - त्रिवेणी बाबा

भिवानी। पृथ्वी पर निरंतर बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए विद्यार्थी वर्ग विभिन्न प्रकार से अपना योगदान दे सकते है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अपना जन्मदिन पर्यावरण को समर्पित करते हुए मनाना चाहिए तथा अपने जन्मदिन या किसी भी अवसर पर कम से कम दो पौधे रोपित कर उसका संरक्षण भी करना चाहिए।

यह बात त्रिवेणी बाबा ने स्थानीय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल में त्रिवेणी रोपित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधें पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते है। यदि फेफड़े स्वच्छ होंगे तो शरीर बीमारियों से बचा रहेगा। उसी प्रकार अधिक से अधिक पौधों का रोपण व संरक्षण कर हम पृथ्वी के पर्यावरण को भी बचा सकते है। जिसकी वजह से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्या एवं स्कूल स्टाफ के सदस्यों के साथ शंकर नर्सरी संचालक चंद्रमोहन भी मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008